1989 Shri Mohammad Yunus

1990 Shri Jagmohan

" Shri Prakash Yashwant Ambedkar 1990 Shri Bhupinder Singh Mann Shri R.K. Karanjia

1993 Dr. M. Aram " Dr. Bidhu Bhushan Dutta

Smt. Vyjayantimala Bali " Shri Maulana Habib-ur-Rehman

Shri Mahendra Prasad

दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध को दिल्ली सरकार को सौंपना

402. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोलाः**
श्री नागमणिः

क्या जल-भूतल पविहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध को दिल्ली सरकार को सौंपने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या समग्र घाटे को अंतरित करने का भी कोई प्रस्ताव है?

जल-भूतल पविहन मंत्री (श्री टी॰ जी॰ वेंकटराधन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) हस्तांतरण की रूप-रेखाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के संबंध में भारत-चीन के बीच विचार-विमर्श

403. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और चीन ने सुरक्षा संबंधी मुद्दों, विशेषकर सीमापार नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में विस्तृत विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) काफी समय से लम्बित सुरक्षा और अपराध संबंधी मुद्दों का किस हद तक समाधान हुआ है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद फकरूल डार): (क) से (ग) गृह मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जुलाई, 1995 में चीन का दौरा किया था। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। चीन के लोक सुरक्षा मंत्री के साथ हुई एक बैठक में गृह मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सभी प्रकार के संगठित अपराधों पर काबू पाने के लिए एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की बात पर बल दिया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि शस्त्र, विस्फोटक और मादक पदार्थ, भारत के लिए चिंता के विषय है।

गुजरात के पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए दूरसंचार

404. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेलः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

संचार मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा: (क) विभाग ने देश के आदिवासी क्षेत्रों, जिनमें गुजरात के आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए आदिवासी उप योजना बनाई है। वर्ष 1996-97 के दौरान गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज स्विचन क्षमता की कुल लगभग 14500 अतिरिक्त लाइनों की योजना बनायी गयी है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से कोई योजना नहीं बनायी गयी है बल्कि राज्य की समग्र योजना के भाग के रूप में है।

(ख) जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।